www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-2* *Issue-10 (Special Issue)* *October 2025*

आदिवासी शिक्षा का सशक्तिकरणः सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का योगदान

डॉ. नीलम सिंह

सहायक प्रोफेसर (अतिथि संकाय), डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

सार–

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है (जनगणना, 2011)। इन समुदायों का एक बड़ा वर्ग आज भी सामाजिक–आर्थिक विकास की मुख्यधारा से अलग है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक रही है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर 59% थी, जिसमें पुरुषों की दर 68.5% जबकि महिलाओं की केवल 49.4% रही। यह असमानता दर्शाती है कि आदिवासी महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना आज भी एक प्रमुख चुनौती है। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा सबसे प्रभावशाली सशक्तिकरण का साधन है। इसी दृष्टि से सरकार ने कई योजनाएँ चलाईंकृजैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), आश्रम शालाएँ, जनजातीय उप–योजना (TSP), छात्रवृत्ति योजनाएँ तथा डिजिटल शिक्षा पहलेंकृजिनसे आदिवासी विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता बढ़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने भी आदिवासी शिक्षा को नए आयाम दिए हैं। इसमें मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा, स्थानीय संस्कृति पर आधारित पाठ्यचर्या, लैंगिक समानता को बढ़ावा और डिजिटल संसाधनों की सुलभता जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन प्रयासों ने न केवल साक्षरता दर में सुधार लाया है बल्कि महिलाओं की भागीदारी, रोजगार अवसर और सामाजिक सशक्तिकरण की संभावनाएँ भी बढ़ाई हैं।

हालाँकि, उच्च ड्रॉपआउट दर, डिजिटल असमानता और उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए आवश्यक है कि भविष्य की नीतियाँ इन मुद्दों पर और गहन कार्य करें, ताकि अनुसूचित जनजातियाँ विशेषकर महिलाएँ गुणवत्तापूर्ण, समान और सतत शिक्षा से पूर्णतः लाभान्वित हो सकें।

मुख्य शब्द– अनुसूचित जनजाति, शिक्षा नीति 2020, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल असमानता, ड्रॉपआउट दर

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास और सामाजिक प्रगति में शिक्षा को आधारभूत शक्ति माना जाता है। यह केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमुख मार्ग है। शिक्षा व्यक्ति को जागरूक और समर्थ बनाती है तथा समाज में न्याय और समान अवसर स्थापित करने में मदद करती है। इसी कारण इसे प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। विशेष रूप से उपेक्षित एवं हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी सशक्तिकरण का माध्यम है। भारत में जनजातीय शिक्षा को मानव संसाधन विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा माना गया है, क्योंकि यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारती है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से भी जोड़ती है।

भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समुदायों की अपनी अलग और विशिष्ट पहचान है। विश्व की कुल जनजातीय आबादी का लगभग एक–तिहाई भारत में बसता है। यहाँ 10.45 करोड़ (8.6%) से अधिक अनुसूचित जनजातीय लोग 705 समुदायों में निवास करते हैं। इनमें से लगभग 2.6 मिलियन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से संबंधित हैं, जिन्हें "आदिम जनजातियाँ" भी कहा जाता है। वर्तमान

में देश के 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 75 PVTGs समूह रहते हैं, जिनकी अधिक उपस्थिति 90 जिलों और 809 ब्लॉकों में दर्ज की गई है, जहाँ आदिवासी जनसंख्या 50:% से अधिक है।

यद्यपि ये समुदाय सदियों से अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते आए हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा से उनका जुड़ाव अपेक्षाकृत सीमित रहा है। उपनिवेशकालीन नीतियों, स्वतंत्रता के बाद किए गए शैक्षिक प्रयासों और सरकारी योजनाओं के बावजूद ये कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। भौगोलिक अलगाव, आर्थिक अभाव, भाषा संबंधी अवरोध, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, स्थानीय संदर्भों से असंगत पाठ्यचर्या और नीतिगत कमियाँकृये सभी कारण आदिवासी शिक्षा के मार्ग में बाधक बने हुए हैं।

इन्हीं जटिलताओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध का उद्देश्य आदिवासी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन करना है। यह शोध विशेष रूप से इस बात की पड़ताल करता है कि किस प्रकार सरकारी योजनाएँ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदिवासी समुदायों, खासकर महिलाओं, को शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में नए अवसर प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही यह अध्ययन चुनौतियों, संभावनाओं और शासकीय हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में आदिवासी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और सरकारी योजनाओं व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का आकलन करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1. अनुसूचित जनजातियों के लिंग आधारित शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. आदिवासी समुदायों को शिक्षा से जोड़ने हेतु केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आदिवासी शिक्षा की चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना।
4. भविष्य में आदिवासी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की प्रासंगिकता

भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, किंतु आज भी शिक्षा के क्षेत्र में ये समुदाय पिछड़े हुए हैं। विशेष रूप से महिला शिक्षा का स्तर अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सामूहिक सशक्तिकरण का भी माध्यम है। इसलिए आदिवासी शिक्षा की स्थिति को समझना और उसे सुधारने के लिए नीतिगत पहल की समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है।

यह शोध निम्न बिंदुओं के कारण प्रासंगिक है–

1. यह अध्ययन आदिवासी शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का व्यापक विश्लेषण करता है।
2. सरकारी योजनाओं और नीतिगत हस्तक्षेपों की वास्तविक प्रभावशीलता को सामने लाता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं को आदिवासी शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट करता है।

नीति निर्माताओं, शिक्षा शास्त्रियों और शोधकर्ताओं को भविष्य की रणनीतियाँ बनाने में उपयोगी संकेत प्रदान करता है। सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों को जोड़ते हुए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

अनुसंधान पद्धति

इस शोध में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिन्हें विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से संकलित किया गया है। मुख्य स्रोतों में शिक्षा मंत्रालय की न्क्प्म्+ रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज़, नीतिगत प्रतिवेदन, तथा आदिवासी शिक्षा पर केंद्रित विद्वानों के शोध–पत्र और पुस्तकों को शामिल किया गया है। अध्ययन में अनुसूचित जनजातियों के नामांकन आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि समय के साथ उनकी शैक्षिक भागीदारी में किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

Level of Education	Overall GER (%)	Male GER (%)	Female GER (%)
Primary (1 to 5)	98.0	98.6	98.3
Upper Primary (6 to 8)	94.8	95.6	95.2
Elementary (1 to 8)	96.8	97.4	97.1
Secondary (9-10)	75.4	78.5	76.9

Source: Education for All in India

GER of Scheduled Tribes Children at All-India Level, UDISE Plus 2023-24

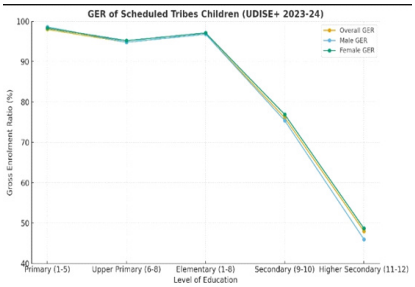

Data Representation of GER of Scheduled Tribes Children at All India

आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष

उपरोक्त आँकड़े और चार्ट स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन लगभग सार्वभौमिक है, परंतु माध्यमिक स्तर पर यह घटकर 76% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मात्र 49: रह जाता है। यह दर्शाता है कि प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़ने में आदिवासी बच्चों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सभी स्तरों पर लड़कियों की नामांकन दर लड़कों से अधिक है। यह प्रवृत्ति आदिवासी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिलाओं की बढ़ती शैक्षिक भागीदारी की ओर संकेत करती है।

सरकारी योजनाएँ और पहल

आवासीय विद्यालयों जैसे एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (EMRS), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), आश्रम विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय ने दूरस्थ आदिवासी अंचलों में शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित किया है। इन विद्यालयों ने विशेष रूप से बालिकाओं की भागीदारी और निरंतरता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके साथ ही, मैट्रिक/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय फैलोशिप, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय साधन–सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना जैसी पहलें सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुँचने में सहायक रही हैं।

डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समावेशन की दृष्टि से ई–पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सवबंसप्रमक डव्ब्े तथा NESTS और UNICEF का "तलाश कार्यक्रम" विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधन प्रदान कर उनके समग्र विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना (2018–19) ने स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने, नए विद्यालयों और कक्षाओं के निर्माण तथा समावेशी वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं, पीएम पोषण योजना ने बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराकर उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार किया है तथा NIOS/SIOS जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं ने शिक्षा अधूरी रह जाने वाले बच्चों को उसे पूरा करने का अवसर दिया है।

NEP 2020 और जनजातीय शिक्षा में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसमें बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जिससे न केवल शिक्षा की समझ बेहतर हो सके बल्कि आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाते हुए इसमें स्थानीय ज्ञान, कौशल और परंपराओं को शामिल किया गया है ताकि शिक्षा

बच्चों के जीवन से जुड़ी और प्रासंगिक बने। दूरदराज़ क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना तथा स्थानीय समुदायों से शिक्षकों की भर्ती पर बल दिया गया है। समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने के साथ–साथ लचीला और प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें बच्चों की सांस्कृतिक धरोहर को विशेष महत्व दिया गया है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों और फैलोशिप्स का प्रावधान किया गया है जिससे युवाओं की भागीदारी बढ़े, वहीं कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी युवाओं की रोजगार क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हालाँकि इन प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आदिवासी छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जाती है जिसका मुख्य कारण आर्थिक कठिनाइयाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और विद्यालयों तक पहुँच की कमी है। विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में उच्च माध्यमिक स्तर पर सहभागिता घटती है। भौगोलिक और संसाधन संबंधी समस्याएँ जैसे दूरदराज़ और पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों तथा बुनियादी ढाँचे की कमी भी एक बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त डिजिटल और भाषा संबंधी सीमाएँ, जैसे इंटरनेट तक सीमित पहुँच और मातृभाषा आधारित शिक्षा की कमी, आदिवासी शिक्षा के सामने गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

सुझाव

छात्रावास और बुनियादी सुविधाएँः महिला आदिवासी छात्रों के लिए सुरक्षित और समर्पित छात्रावासों की स्थापना की जाए। इनमें पीने का पानी, स्वच्छता और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित हों, विशेषकर दूरदराज़ क्षेत्रों में। ड्रॉपआउट की समस्या कम करने के लिए छात्रवृत्ति, यात्रा भत्ता और आवासीय सुविधाओं में वृद्धि की जाए। छात्राओं के लिए नियमित मेंटरशिप और काउंसलिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः शिक्षकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ जिनसे वे आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति संवेदनशील बन सकें। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो। साथ ही, दूरदराज़ क्षेत्रों के EMRS और अन्य आवासीय विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाए।

डिजिटल शिक्षा और भाषा समावेशः ई–पाठशाला, डिजिटल लाइब्रेरी और प्ब्ज् उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे छात्रों की सीखने की क्षमता और समझ में सुधार हो।

नीति और योजना का समन्वयः NEP 2020 तथा अन्य केंद्र और राज्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। SC/ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, यूनिफ़ॉर्म, पुस्तकें और परिवहन सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई जाएँ।

समन्वय और निगरानी तंत्रः सरकारी और गैर–सरकारी पहलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तव में लक्षित समुदाय तक पहुँच सके।

निष्कर्ष–

आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति के बावजूद, आदिवासी समुदाय अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उच्च ड्रॉप–आउट दर, अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और सांस्कृतिक दूरी आदिवासी छात्रों की शिक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता में बाधा डाल रही हैं। यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि मौलिक अधिकारों में शामिल शिक्षा तक उनकी पहुँच अभी भी सीमित है और समाज के हाशिए पर खड़े समूहों के लिए शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

फिर भी, सरकारी योजनाओं और नीतियों जैसे EMRS, छात्रवृत्ति और आवासीय विद्यालयों ने आदिवासी शिक्षा की पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। NEP 2020 ने मातृभाषा, बहुभाषिकता और समावेशी दृष्टिकोण को प्रमुखता देकर आदिवासी शिक्षा को नई दिशा दी है। यदि इन योजनाओं और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो आदिवासी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों और सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है। यह दर्शाता है कि सही प्रयास और संसाधन मिलने पर आदिवासी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any

errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Bramanandam, T (2016) studied on educational status among the schedule tribes: issues and challenges. The NEHU journal. 0972-8406, 15(2), 69-85.
2. Dash, D. K. (2023). Problems of Tribal Education in India: An Analysis. In Education as Development (pp. 121-130). Routledge India.
3. Garg, M. K., Chowdhury, P., & Sheikh, I. (2023). Determinants of school dropouts in India: a study through survival analysis approach. Journal of Social and Economic Development, 1-23.
4. Kumari, Vibhuti Nayak & Randhir Kumar (2022) In Pursuit of Education: Why Some Tribal Girls Continue and Others Dropout of Schools in Rural India?
5. Ministry of Tribal Affairs. (2019). Annual Report 2018–19. Government of India.
6. Mitra, A. & Singh, P. (2008) Trends in literacy rates and schooling among the scheduled tribe women in india
7. Naik, J., Majhi, R., & Dana Sanna, P. (2021). Education and Empowerment of Tribal Communities in India. Journal of Social Development Studies, 17(2), 45–57.
8. Radhakrishnan, Aiswarya and Pillai, Nisanth. M. (2018). Awareness and Effectiveness of Educational Schemes for Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Coimbatore District. https://acadpubl.eu/hub/2018-119-15/4/605.pdf
9. Sharma, A. (2022). Impact of National Education Policy 2020 on Tribal Education in India. International Journal of Educational Research, 40(1), 112–128.
10. Sucharita, V. (2023). Tribal Education in India–Reviewing the Progress and the Way Forward. Journal of Asian and African Studies, 00219096231219759.
11. Swati Sonavane & V. V. Kulkarni (2024) Educational attainment and problems in Indian Tribal Populations, with a focus on Tribal Women: A Theoretical Assessment
12. World Bank. (2023). State of Education in Tribal India. Washington, DC: World Bank.
13. अनुसूचित जनजातियों के सांख्यिकीय प्रोफाइल (2013), जनजातीय कार्य मंत्रालयः नई दिल्ली भारत सरकार।
14. उप्पल, श्वेता 2010, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याएँः नई दिल्ली– एन. सी.ई.आर.टी.।
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Cite this Article

'डॉ. नीलम सिंह', "आदिवासी शिक्षा का सशक्तिकरणरू सरकारी योजनाओं और रा□ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का योगदान", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10 (Special Issue), October 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

Published Date- 31 October 2025